



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 439।

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 6, 2010/श्रावण 15, 1932

No. 439।

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 6, 2010/SHRAVANA 15, 1932

गृह मंत्रालय

(केन्द्र-राज्य प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2010

सा.का.नि. 661(अ).—कैदी सम्प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 (2003 का 49) की धारा 3 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका के लिए लागू होंगे तथा उस देश और भारत के बीच कैदियों के अन्तरण के लिए भारत गणराज्य की सरकार और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका की सरकार के बीच हुई संधि के पाठ को निम्न प्रकार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

दण्डित व्यक्तियों के अन्तरण के संबंध में

भारत गणराज्य की सरकार

तथा

डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका की सरकार

के बीच करार

भारत-गणराज्य की सरकार तथा डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका की सरकार, जिन्हें इसमें इसके बाद “संविदाकार देश” कहा गया है;

दण्डित व्यक्तियों का उनके स्वयं के देशों में सामाजिक पुनर्वास सुगम बनाने की अभिलाषा से; और

यह मानते हुए कि यह उद्देश्य, किसी अन्य संविदाकार देश में कोई अपराध करने के परिणामस्वरूप दोषसिद्ध और दंडित किए गए संविदाकार देश के राष्ट्रिकों को उनके स्वयं के देश में सज्जा काटने का अवसर प्रदान करके पूरा किया जाना चाहिए;

निम्न प्रकार सहमत हो गई हैं :

अनुच्छेद 1परिभाषा

इस करार के प्रयोजनार्थ :

- (क) “निर्णय” से तात्पर्य न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के किसी ऐसे निर्णय अथवा आदेश से है जिसके तहत दण्ड दिया गया हो;
- (ख) “प्राप्तकर्ता देश” से तात्पर्य उस देश से है जिसको दण्डित व्यक्ति सज़ा काटने के प्रयोजन से अंतरित किया जा सकता हो अथवा अंतरित किया गया हो;
- (ग) “दण्ड” से तात्पर्य किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा अपने दांडिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए निर्धारित समयावधि के लिए या आजीवन के लिए आजादी से वंचित रखे जाने का कोई दंड या उपाय है;
- (घ) “दण्डित व्यक्ति” से तात्पर्य अंतरणकर्ता देश में तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा स्थापित न्यायालयों सहित किसी दांडिक न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय के अनुसरण में कारावास की सज़ा काट रहे व्यक्ति से है;
- (ङ) “अंतरणकर्ता देश” से तात्पर्य उस देश से है जिसमें उस व्यक्ति को दंड दिया गया हो जिसे अंतरित किया जा सकता हो या जिसे अंतरित कर दिया गया हो; और
- (च) “राष्ट्रिक” से तात्पर्य दोनों में से किसी संविदाकार देश के नागरिक से है।

अनुच्छेद 2सामान्य सिद्धांत

- संविदाकार देशों के कानूनों और इस करार के प्रावधानों के अनुसार कोई संविदाकार देश के भू-भाग में दंडित किसी व्यक्ति को सज़ा काटने के लिए दूसरे संविदाकार देश के भू-भाग में अंतरित किया जा सकता है ताकि वह उसे दी गई सज़ा काट सके। इस संबंध में दंडित व्यक्ति इस करार के अंतर्गत या तो अन्तरणकर्ता देश या प्राप्तकर्ता देश से ऐसे अंतरण के लिए अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है।

2. अंतरण का अनुरोध किसी दंडित व्यक्ति द्वारा जो संविदाकार देश का राष्ट्रिक हो या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उसकी ओर से कार्रवाई करने का पात्र हो, संबंधित संविदाकार देश के कानूनों के अनुसार और यथानिर्धारित ढंग से आवेदन कर सकता है।

अनुच्छेद 3

अंतरण की शर्तें

इस क्रार के अंतर्गत किसी दंडित व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों पर ही अन्तरित किया जा सकता है :

- (क) वह व्यक्ति प्राप्तकर्ता देश का नागरिक हो;
- (ख) दंडित व्यक्ति को मृत्युदण्ड नहीं दिया गया हो;
- (ग) निर्णय अंतिम हो;
- (घ) अन्तरणकर्ता देश में दंडित व्यक्ति के विरुद्ध कोई जांच, विचारण अथवा किसी अन्य प्रकार की कार्रवाई लम्बित नहीं हो;
- (ङ) अंतरण के अनुरोध की प्राप्ति के समय दंडित व्यक्ति द्वारा भोगी जाने वाली शेष सज्जा की अवधि कम से कम छः माह बची हो अथवा वह आजीवन कारावास की सज्जा काट रहा हो;
- (च) जिन कृत्यों अथवा गलतियों के लिए उस व्यक्ति को अंतरणकर्ता देश में दंड दिया गया था, वे प्राप्तकर्ता देश में दंडनीय अपराध हों अथवा यदि इसके भूम्भाग में घटित होता है तो यह एक दांडिक अपराध होगा;
- (छ) दंडित व्यक्ति को सैन्य कानून के तहत दंडित न किया गया हो;
- (ज) प्राप्तकर्ता देश में दंडित व्यक्ति की हिरासत को अंतरित करने से अंतरणकर्ता देश की संप्रभुता, सुरक्षा अथवा किसी अन्य हित पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो;
- (झ) अंतरण के संबंध में दंडित व्यक्ति द्वारा सहमति दी जाती है अथवा किसी भी संविदाकार देश द्वारा दंडित व्यक्ति की आयु अथवा शारीरिक या अनुरोध;

मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर जरूरी समझे जाने पर संविदाकार देश के कानून के अनुसरण में उस व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए हकदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सहमति दी गई हो; और

- (ज) अंतरणकर्ता और प्राप्तकर्ता देश अंतरण के संबंध में सहमत हों।

अनुच्छेद 4

सूचना भेजने का दायित्व

1. यदि दंडित व्यक्ति ने अंतरणकर्ता देश को इस करार के तहत अन्तरित होने की इच्छा व्यक्त की हो तो अंतरणकर्ता देश प्राप्तकर्ता देश को निम्नलिखित सूचना तथा दस्तावेज़ भेजेगा बशर्ते कि प्राप्तकर्ता या अंतरणकर्ता देश में से किसी के भी द्वारा पहले ऐसा कोई निर्णय न लिया गया हो कि वह अंतरण के लिए सहमत नहीं है :

- (क) दंडित व्यक्ति का नाम और राष्ट्रीयता, जन्म तिथि एवं जन्म स्थान;
- (ख) प्राप्तकर्ता देश में उसका पता, यदि कोई हो;
- (ग) उन तथ्यों का विवरण जिन पर दंड आधारित था;
- (घ) दंड की प्रकृति, सम्यावधि एवं प्रारंभ होने की तारीख;
- (ङ) निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा कानून के उन संगत उपबंधों की एक प्रति जिनके अंतर्गत दंडित व्यक्ति के खिलाफ दंड पारित किया गया;
- (च) दंडित व्यक्ति की कोई डाक्टरी, सामाजिक अथवा अन्य कोई रिपोर्ट, जहां वह उसके आवेदन के निपटान अथवा उसकी परिरुद्धता की प्रकृति के निर्णय के लिए प्रासंगिक हो;
- (छ) कोई अन्य जानकारी जिसके लिए प्राप्तकर्ता देश यह विनिर्दिष्ट करे कि यह संबंधित मामले में अंतरण की संभावना पर विचार करने के लिए जरूरी है और जिससे वह अपने कानून के अंतर्गत दंडित व्यक्ति को अंतरण के सम्पूर्ण परिणामों की जानकारी देने में सक्षम हो सके;
- (ज) अंतरित किए जाने वाले दंडित व्यक्ति अथवा अंतरणकर्ता देश के कानून के अनुसरण में उसकी ओर से कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति का

(ज्ञ) किसी विचारण पूर्व नजरबंदी, क्षमा या दंड प्रवर्तन के लिए संगत किसी अन्य तथ्य को शामिल करते हुए एक विवरण पत्र जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि कितना दंड पूरा हो चुका है।

2. इस करार के अधीन किसी अनुरोध पर कोई भी निर्णय लिए जाने के प्रयोजन से प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश को निम्नलिखित जानकारी एवं दस्तावेज़ तभी भेजेगा बशर्ते कि प्राप्तकर्ता या अंतरणकर्ता देश ने पहले ही यह निश्चय कर लिया हो कि वह अंतरण से सहमत नहीं है :

- (क) एक विवरण अथवा दस्तावेज़ जो यह दर्शाता हो कि दंडित व्यक्ति प्राप्तकर्ता देश का एक नागरिक है;
- (ख) प्राप्तकर्ता देश के संगत कानूनी प्रावधानों की एक प्रति जिसमें ऐसे कृत्यों अथवा चूंके, जिनके कारण अंतरणकर्ता देश में दण्ड लगाया गया है, वे प्राप्तकर्ता देश में दण्डनीय अपराध भी माने गए हों अथवा यदि, ऐसे कृत्य अथवा चूंके इसके भू-भाग में घटित हों, तो उसे दण्डनीय अपराध माना जाएगा;
- (ग) दंडित व्यक्ति के अन्तरण पर इस करार के अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 2 के प्रभाव का विवरण, यदि लागू हो, के सहित उसके अन्तरण के बाद प्राप्तकर्ता देश में सज़ा की अवधि एवं प्रवर्तन संबंधी किसी कानून अथवा विनियम के प्रभाव का विवरण;
- (घ) दण्डित व्यक्ति के अंतरण को स्वीकार करने के लिए प्राप्तकर्ता देश की सहमति और दंडित व्यक्ति की सज़ा के बाकी बचे हिस्से को शासित करने हेतु एक वचनबद्धता; तथा
- (ङ) कोई अन्य सूचना अथवा दस्तावेज़ जिसे अंतरणकर्ता देश आवश्यक समझे।

अनुच्छेद 5

अनुरोध एवं जवाब

1. अंतरण के लिए अनुरोध लिखित रूप में, निर्धारित प्रपत्र, यदि कोई हो, में प्रस्तुत किया जाएगा और राजनयिक माध्यम के द्वारा एक संविदाकार देश के केन्द्रीय प्राधिकारी के माध्यम से दूसरे संविदाकार देश के केन्द्रीय प्राधिकारी को सम्बोधित किया जाएगा। जवाब उसी माध्यम से सूचित किए जाएंगे।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के प्रयोजन हेतु :

- भारत-गणराज्य के संबंध में गृह मंत्रालय; और
 - डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका के लिए, न्याय और विधि सुधार मंत्रालय के संबंध में न्याय मंत्रालय, केन्द्रीय प्राधिकारी होंगे।
3. प्रार्थित संविदाकार देश शीघ्रतापूर्वक अनुरोधकर्ता संविदाकार देश को अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगा कि वह प्रार्थित अंतरण के लिए सहमत है अथवा नहीं।

अनुच्छेद 6

सहमति और इसका सत्यापन

1. अंतरणकर्ता देश यह सुनिश्चित करेगा कि इस करार के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 1 (i) के अनुसार अंतरण के लिए सहमति देने वाला व्यक्ति, ऐसा स्वेच्छा से तथा इसके कानूनी परिणामों की पूरी जानकारी के साथ कर रहा है।
2. अंतरणकर्ता देश, प्राप्तकर्ता देश को यह सत्यापित करने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा कि सहमति, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में दी गई शर्तों के अनुसार दी गई है।

अनुच्छेद 7

प्राप्तकर्ता देश के लिए अंतरण का प्रभाव

1. प्राप्तकर्ता देश के सक्षम प्राधिकारी, न्यायालय अथवा प्रशासनिक आदेश, जैसा भी इसके राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपेक्षित हो, के माध्यम से इस करार के अनुच्छेद 8 में दी गई शर्तों के अंतर्गत सज्ञा के प्रवर्तन को जारी रखेंगे।
2. इस करार के अनुच्छेद 10 के प्रावधानों के अध्यधीन, सज्ञा का प्रवर्तन प्राप्तकर्ता देश के कानून द्वारा शासित किया जाएगा और सिर्फ वही देश समस्त समुचित निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा।

अनुच्छेद 8

सज्ञा का सतत प्रवर्तन

1. प्राप्तकर्ता देश, अंतरणकर्ता देश द्वारा यथा-अभिनिर्धारित सज्ञा की कानूनी प्रकृति एवं अवधि द्वारा आबद्ध होगा।

2. तथापि, यदि सज्ञा की प्रकृति अथवा अवधि अथवा दोनों ही प्राप्तकर्ता देश के कानून से असंगत हों, अथवा इसके कानून में ऐसा अपेक्षित हो, तो प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश की सहमति से न्यायालय अथवा प्रशासनिक आदेश द्वारा सज्ञा को अपने स्वयं के कानून द्वारा निर्धारित दण्ड अथवा उपाय में रूपान्तरित कर सकेगा। जहां तक इसकी प्रकृति एवं अवधि का प्रश्न है, रूपान्तरित दण्ड अथवा उपाय, यथासंभव, अंतरणकर्ता देश के अधिनिर्णय द्वारा आरोपित सज्ञा के अनुरूप होगा। तथापि, यह अपनी प्रकृति अथवा अवधि द्वारा अंतरण देश में आरोपित की गई, सज्ञा में वृद्धि नहीं करेगा।

अनुच्छेद 9

अंतरणकर्ता देश के लिए सज्ञा के समापन का प्रभाव

जब प्राप्तकर्ता देश इस क्रार के अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 1 (क) के तहत अंतरणकर्ता देश को यह अधिसूचित करता है कि सज्ञा पूरी हो गयी है तो ऐसी अधिसूचना अंतरणकर्ता देश में उस सज्ञा के निरसन में प्रभावी होगी।

अनुच्छेद 10

माफी, राजक्षमा अथवा लघुकरण और निर्णय की समीक्षा

1. केवल अंतरणकर्ता देश ही निर्णय की पुनरीक्षा के लिए किसी आवेदन-पत्र पर निर्णय
2. जब तक अन्यथा अंतरणकर्ता देश सहमत न हो, केवल अंतरणकर्ता देश ही अपने संविधान अथवा अन्य कानूनों के अनुरूप दंड की माफी, राजक्षमा प्रदान कर सकेगा अथवा दण्ड का लघुकरण कर सकेगा।

अनुच्छेद 11

दण्ड के प्रवर्तन की समाप्ति

जैसे ही अंतरणकर्ता देश द्वारा किसी भी ऐसे फैसले अथवा उपाय की सूचना दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप दण्ड का प्रवर्तन समाप्त किया गया हो, तो प्राप्तकर्ता देश दण्ड के प्रवर्तन को समाप्त कर देगा।

अनुच्छेद 12

दण्ड के प्रवर्तन संबंधी सूचना

1. प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश को अधिसूचित करेगा :
- (क): जब दण्ड का प्रवर्तन पूरा कर लिया गया हो; अथवा-

- (ख): यदि दण्ड का प्रवर्तन पूरा होने से पहले दंडित व्यक्ति हिरासत से भाग जाता है।
2. ऊपर 1 (ख) की घटना की स्थिति में प्राप्तकर्ता देश को चाहिए कि वह दंडित व्यक्ति की गिरफ्तारी का हर-सभव प्रयास करे ताकि वह स्वयं को मिले दण्ड का शेष भाग पूरा कर सके और प्राप्तकर्ता देश के संगत कानून के अन्तर्गत किए गए अपराध के लिए अभियोग चलाया जा सके। अंतरणकर्ता देश को ऐसे उपायों के परिणामों से अवगत कराया जाएगा।
 3. यदि अंतरणकर्ता देश द्वारा अपेक्षित हो तो प्राप्तकर्ता देश दण्ड के प्रवर्तन के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

अनुच्छेद 13

अभिवहन

1. यदि कोई भी संविदाकार देश दंडित व्यक्तियों के अंतरण के लिए किसी तीसरे देश के साथ कोई व्यवस्था करता है तो दूसरा संविदाकार देश ऐसी व्यवस्था के अनुसरण में अपने भू-भाग से अंतरित किए जाने वाले दंडित व्यक्तियों के अभिवहन को सुकर बनाने में सहयोग करेगा। सिवाय इसके कि वह किसी ऐसे दंडित व्यक्ति के अभिवहन से इंकार करें जो वहीं का राष्ट्रिक हो।
2. ऐसे अंतरण का इच्छुक संविदाकार देश दूसरे संविदाकार देश को ऐसे अभिवहन के बारे में अग्रिम नोटिस देगा।

अनुच्छेद 14

लागत

अंतरणकर्ता देश के अनन्य भू-भाग में होने वाले व्ययों को छोड़कर, इस क़रार को लागू करने एवं क्रियान्वित करने में आने वाले सभी व्यय प्राप्तकर्ता देश द्वारा वहन किए जाएंगे। तथापि, प्राप्तकर्ता देश अंतरण में होने वाले व्यय की सम्पूर्ण अथवा आंशिक वसूली दंडित व्यक्ति अथवा किसी अन्य संसाधन से कर सकता है।

अनुच्छेद 15

भाषा

अनुरोध एवं सहायक दस्तावेज अंग्रेजी में होंगे अथवा उसके साथ अंग्रेजी अनुवाद लगा होगा।

अनुच्छेद 16

लागू होने का दायरा

यह क़रार इसके प्रभावी होने की तारीख से पहले या बाद में लगाए गए दण्ड के प्रवर्तन पर लागू होगा।

अनुच्छेद 17संशोधन

संविदाकार देशों द्वारा सहमत इस क्रार में कोई संशोधन अथवा आशोधन उसी प्रकार से प्रभावी होंगे जिस प्रकार इस करार को प्रभावी करने के लिए लागू किए जाएंगे।

अनुच्छेद 18अंतिम प्रावधान

1. यह क्रार, अनुसमर्थन के अध्ययीन होगा तथा अनुसमर्थन के लिखित का आदान-प्रदान करने की तारीख से प्रभावी होगा।
2. यह क्रार, किसी भी संविदाकार देश द्वारा दूसरे संविदाकार देश को क्रार के परिसमापन के अपने आशय की लिखित सूचना दिए जाने की तारीख से छह माह तक प्रभावी रहेगा।
3. किसी भी परिसमापन के बावजूद यह क्रार उन दंडित व्यक्तियों के दंडों के प्रवर्तन पर लागू रहेगा जिन्हें इस परिसमापन के लागू होने की तारीख से पहले इस क्रार के अंतर्गत अंतरित किया गया हो।

इस क्रार के साक्ष्य के रूप में अपनी-अपनी सरकारों द्वारा इस संबंध में उचित प्रकार से प्राधिकृत किए जाने पर अधोहस्ताक्षरी ने इस क्रार पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके सभी पाठ समान रूप से अधिप्रमाणित होने के नाते इसे नई दिल्ली में दिनांक 09 जून, 2010 को अंग्रेजी, हिन्दी और सिंहला भाषा की दो-दो मूल प्रतियों में तैयार किया गया है। व्याख्या में मतभेद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत-गणराज्य की
सरकार की ओर से

डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ
श्रीलंका की सरकार की ओर से

[फा. सं. 17011/10/2005-पी आर]
डॉ. निर्मलजीत सिंह कलसी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(C S DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2010

G.S.R. 661(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections(1) and (2) of section 3 of the Repatriation of Prisoners Act, 2003 (49 of 2003), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and notifies the text of the agreement entered into between the Government of the Republic of India and the Government of Democratic Socialist Republic of Sri Lanka for the transfer of prisoners between that country and India as follows, namely :-

**AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA
AND
THE GOVERNMENT OF
THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA
ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS**

The Government of the Republic of India and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, hereinafter referred to as the “Contracting States”;

Desiring to facilitate the social rehabilitation of sentenced persons into their own countries; and

Considering that this objective should be fulfilled by giving nationals of a Contracting State, who have been convicted and sentenced in the other Contracting State as a result of the commission of a criminal offence, the opportunity to serve the sentence in their own country;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1
Definitions

For the purpose of this Agreement:

- (a) “**judgment**” means a decision or order of a court or tribunal imposing a sentence;
- (b) “**receiving State**” means a State to which the sentenced person may be, or has been, transferred in order to serve the sentence;
- (c) “**sentence**” means any punishment or measure involving deprivation of liberty ordered by a court or tribunal for a determinate period of time or for life imprisonment, in the exercise of its criminal jurisdiction;
- (d) “**sentenced person**” means a person undergoing a sentence of imprisonment pursuant to a judgment by a criminal court including the courts established under the law for the time being in force in the transferring State;
- (e) “**transferring State**” means the State in which the sentence was imposed on the person who may be, or has been transferred; and
- (f) “**national**” means a citizen of either Contracting State.

ARTICLE 2
General principles

1. A person sentenced in the territory of one Contracting State may be transferred to the territory of the other Contracting State in accordance with the laws of the Contracting States and the provisions of this Agreement, in order to serve the sentence imposed on him. To that end, he may express either to the transferring State or the receiving State, his willingness to be transferred under this Agreement.
2. Transfer may be requested by any sentenced person who is a national of a Contracting State or by any other person who is entitled to act on his behalf by making an application to either of the Contracting States, in accordance with the laws of the concerned Contracting State and in the manner so prescribed.

ARTICLE 3

Conditions for transfer

A sentenced person may be transferred under this Agreement only on the following conditions:

- (a) the person is a national of the receiving State;
- (b) the death penalty has not been imposed on the sentenced person;
- (c) the judgment is final;
- (d) no inquiry, trial or any other proceeding is pending against the sentenced person in the transferring State;
- (e) at the time of receipt of the request for transfer, the sentenced person still has at least six months of the sentence to serve or is undergoing a sentence of life imprisonment;
- (f) the acts or omissions for which that person was sentenced in the transferring State are those which are punishable as a crime in the receiving State, or would constitute a criminal offence if committed on its territory;
- (g) the sentenced person has not been convicted for an offence under the military law;
- (h) transfer of custody of the sentenced person to the receiving State shall not be prejudicial to the sovereignty, security or any other interest of the transferring State;
- (i) consent to the transfer is given by the sentenced person or, where in view of his age or physical or mental condition either Contracting State considers it necessary, by any other person entitled to act on his behalf, in accordance with the laws of the Contracting State; and
- (j) the transferring and receiving States agree to the transfer.

ARTICLE 4

Obligation to furnish information

1. If the sentenced person has expressed an interest to the transferring State in being transferred under this Agreement, the transferring State shall send the following information and documents to the receiving State unless either the receiving or the transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:

- (a) the name, nationality, date and place of birth of the sentenced person;

- (b) his address, if any, in the receiving State;
- (c) a statement of the facts upon which the sentence was based;
- (d) the nature, duration and date of commencement of the sentence;
- (e) a certified copy of the judgment and a copy of the relevant provisions of the law under which the sentence has been passed against the sentenced person;
- (f) a medical, social or any other report on the sentenced person, where it is relevant for the disposal of his application or for deciding the nature of his confinement;
- (g) any other information which the receiving State may specify as required, to enable it to consider the possibility of transfer and to enable it to inform the sentenced person of the full consequences of his transfer under its law;
- (h) the request of the sentenced person to be transferred or of a person entitled to act on his behalf in accordance with the law of the transferring State; and
- (i) a statement indicating how much of the sentence has already been served, including information on any pre-trial detention, remission or any other factor relevant to the enforcement of the sentence.
2. For the purposes of enabling a decision to be made on a request under this Agreement, the receiving State shall send the following information and documents to the transferring State unless either the receiving or the transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:
- (a) a statement or document indicating that the sentenced person is a national of the receiving State;
 - (b) a copy of the relevant legal provisions of the receiving State which provides that the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed in the transferring State, also constitute a criminal offence in the receiving State or will constitute a criminal offence if committed on its territory;
 - (c) a statement to the effect of any law or regulation in relation to the duration and enforcement of the sentence in the receiving State after the sentenced person's transfer including, if applicable, a statement to the effect of paragraph 2 of Article 8 of this Agreement on his transfer;

- (d) the willingness of the receiving State to accept the transfer of the sentenced person and an undertaking to administer the remaining part of the sentence of the sentenced person; and
- (e) any other information or document which the transferring State may consider necessary.

ARTICLE 5

Requests and replies

1. Requests for transfer shall be made in writing in the prescribed proforma, if any, and addressed to the Central Authority of one Contracting State by the Central Authority of the other Contracting State through diplomatic channels. Replies shall be communicated through the same channels.
2. For the purpose of paragraph 1 of this Article, the Central Authority shall be:
 - for the Republic of India, the Ministry of Home Affairs; and
 - for the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, the Ministry of Justice and Law Reforms.
3. The requested Contracting State shall promptly inform the requesting Contracting State of its decision whether or not to agree to the requested transfer.

ARTICLE 6

Consent and its verification

1. The transferring State shall ensure that the person required to give consent to the transfer in accordance with paragraph 1(i) of Article 3 of this Agreement, does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof.
2. The transferring state shall afford an opportunity to the receiving state to verify that the consent is given in accordance with the conditions set out in paragraph 1 of this Article.

ARTICLE 7
Effect of transfer for the receiving State

1. The competent authorities of the receiving State shall continue the enforcement of the sentence through a Court or by an administrative order, as may be required under its national law, under the conditions set out in Article 8 of this Agreement.
2. Subject to the provisions in Article 10 of this Agreement, the enforcement of the sentence shall be governed by the law of the receiving State and that State alone shall be competent to take all appropriate decisions.

ARTICLE 8
Continued enforcement of sentence

1. The receiving State shall be bound by the legal nature and duration of the sentence as determined by the transferring State.
2. If, however, the sentence is by its nature or duration or both incompatible with the law of the receiving State, or its law so requires, that State may, by an order of a Court or by an administrative order, with the consent of the transferring State, adapt the sentence to a punishment or measure prescribed by its own law. As to its nature and duration, the punishment or measure shall, as far as possible, correspond with that imposed by the judgment of the transferring State. It shall, however, not aggravate, by its nature or duration, the sentence imposed in the transferring State.

ARTICLE 9
Effect of completion of sentence for the transferring State

When the receiving State notifies the transferring State under paragraph 1(a) of Article 12 of this Agreement that the sentence has been completed, such notification shall have the effect of discharging that sentence in the transferring State.

ARTICLE 10
Pardon, amnesty or commutation and review of judgment

1. The transferring State alone shall decide on any application for the review of the judgment.

2. Unless the transferring State agrees otherwise, the transferring State alone may grant pardon, amnesty or commutation of the sentence in accordance with its Constitution or other laws.

ARTICLE 11

Termination of enforcement of sentence

The receiving State shall terminate enforcement of the sentence as soon as it is informed by the transferring State of any decision or measure as a result of which the sentence ceases to be enforceable.

ARTICLE 12

Information on enforcement of sentence

1. The receiving State shall notify the transferring State:
 - (a) when the enforcement of the sentence has been completed ; or
 - (b) if the sentenced person escapes from custody before enforcement of the sentence has been completed.
2. In the event of the occurrence of 1(b) above, the receiving State shall take measures necessary to secure his arrest for the purposes of serving the remainder of the sentence and to render him liable to the relevant laws of the receiving State. The transferring State shall be informed of the results of such measures.
3. The receiving State shall furnish a report concerning the enforcement of the sentence, if so required by the transferring State.

ARTICLE 13

Transit

1. If either Contracting State enters into arrangements for the transfer of sentenced persons with any third State, the other Contracting State shall cooperate in facilitating the transit through its territory of the sentenced persons being transferred pursuant to such arrangements, except that it may refuse to grant transit to any sentenced person who is one of its own nationals.
2. The Contracting State intending to make such a transfer shall give advance notice to the other Contracting State of such transit.

ARTICLE 14**Costs**

Any costs incurred in the application and implementation of this Agreement shall be borne by the receiving State, except costs incurred exclusively in the territory of the transferring State. The receiving State may, however, seek to recover all or part of the costs of transfer from the sentenced person or from some other source.

ARTICLE 15**Language**

Requests and supporting documents shall be in English or accompanied by a translation into English.

ARTICLE 16
Scope of application

This Agreement shall be applicable to the enforcement of sentences imposed before or after the entry into force of this Agreement.

ARTICLE 17
Amendments

Any amendments or modifications to this Agreement mutually agreed by the Contracting States shall come into effect in the same manner as may be applicable for the entry into force of this Agreement.

ARTICLE 18
Final provisions

1. This Agreement shall be subject to ratification and shall enter into force on the date on which instruments of ratification are exchanged.
2. The Agreement shall continue to remain in force until six months from the date upon which either Contracting State gives written notice to the other Contracting State of its intention to terminate it.
3. Notwithstanding any termination, this Agreement shall continue to apply to the enforcement of sentences of sentenced persons who have been

transferred under this Agreement before the date on which such termination takes effect.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at New Delhi on this ^{9th} day of June 2010 in two originals in the Hindi Sinhala and English languages, all texts being equally authentic. In the event of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

**For the Government of the
Republic of India**

**For the Government of the
Democratic Socialist
Republic of Sri Lanka**

[F. No. 17011/10/2005-PR]
Dr. NIRMALJEET SINGH KALSI, Jt. Secy.